

प्रेषक,

एन०एस०नपलध्याल,

प्रमुख सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून : दिनांक २५ नवम्बर, 2006

विषय: श्री जगमोहन त्यागी, निवासी-बरला, जिला मुजफ्फरनगर (सागर प्रिन्टर्स एण्ड पैकर्स प्रा० लि०) को कॉरोगेटेड बॉक्सेज यूनिट की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम तांशीपुर में कुल ०.३४२० हे० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-७७२/भूमि व्यवस्था-भूमि कय-०६ दिनांक १२ जून, २००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री जगमोहन त्यागी, निवासी-बरला, जिला मुजफ्फरनगर (सागर प्रिन्टर्स एण्ड पैकर्स प्रा० लि०) को कॉरोगेटेड बॉक्सेज यूनिट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(व) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम तांशीपुर में कुल ०.३४२० हे० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

१- केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के फ्लेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

२- केता दैक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-१६७ के परिणाम लागू होंगे।

४- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

५- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

- 6- रपॉट जनिंग क्षेत्र के लिये निर्धारित सिद्धान्तों/ नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
  - 7- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग, यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  - 8- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
  - 9- स्वयं द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग कॉरोगेटेड बॉक्सेज यूनिट की स्थापना के लिये ही किया जायेगा।
  - 10- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता ही, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 2- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)  
प्रमुख सचिव।

#### संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल भण्डल, पौड़ी।
- 5- श्री जगमोहन त्यागी, निवासी- ग्राम- बरला, तहसील- सदर, जिला-गुजफरनगर।
- 6- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)  
अनु सचिव।